प्रकाशनार्थ

पटना, 16 मार्च। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट (आद्री) द्वारा आयोजित **सोशियो–इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स फॉर इडियाज नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स** विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आज से प्रारंभ हुई।

विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेबर पीयर लॉर्ड मेघनाद देसाई ने कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रवासी बिहारियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जब उन्हें बिहार में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था ताकि वे मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ लेकर खुद को बचाए रख सकें। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम ऐसे प्रवासियों की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रभावी प्रणाली बना सकते हैं। साथ ही, बैंकों की गैर–निष्पादित संपत्तियों में बर्बाद हुई भारी मात्रा में धन की जगह समाज को गरीब अवैतनिक महिलाओं के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री त्रिपुरारी शरण, राज्य सूचना आयुक्त, बिहार सरकार ने कहा कि सरकार को कोविड के बाद अपनी नीतियों पर विचार करने की जरूरत है।

द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, न्यू यॉर्क के प्रोफेसर संजय रेड्डी ने समावेशी विकास को एक ऐसे शब्द के रूप में परिभाषित किया जो कि सवाल करता है कि क्या सभी को विकास के बाद लाभ हुआ है? उन्होंने कहा कि समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए भारत को एक लोकतांत्रिक बाजार अर्थव्यवस्था बनने की पहल करनी चाहिए। यह सभी नागरिकों को सहभागी बनाने में सक्षम होती है। किसी को सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे गंभीर क्षेत्रीय असमानताओं वाले देशों में से एक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में आज प्रति व्यक्ति आय बिहार से साढ़े चार गुना अधिक है। 1960 में यह बिहार से दोगुना था। लेकिन 2005 और 2015 के बीच देश में बाल मृत्यु दर और महिला सशक्तीकरण जैसे गैर–आय अभावों में कमी आई है।

प्रोफेसर अजीत सिन्हा ने कहा कि सार्वभौमिक बुनियादी आय की गारंटी के लिए देश में कुल पूंजी का 10 प्रतिशत समाजीकरण किया जा सकता है। यह ऑटोमेशन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी के कारण आय की कमी की समस्या को हल कर सकता है।

प्रोफेसर जी. ओंकारनाथ ने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि 70 के दशक तक भारत एक असंभव कल्याणकारी राज्य में बदल गया था। स्वतंत्रता के बाद से पारंपरिक शिल्प उद्योग के आधुनिकीकरण की उपेक्षा की गई थी। प्रोफेसर रोमर कोरिया ने उन विवादास्पद मुद्दों पर विचार किया जो नकदी के बजाय पैसे के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होते हैं।

डा. प्रेम चंद्रावरकर ने शहरों की प्रशंसा की क्योंकि वहां लोगों को गुमनाम रहने की सुविधा के चलते स्वतंत्रता मिलती है। यह आजादी गांवों में नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम शहर का प्रबंधन कैसे करते हैं, वह निर्धारित करेगा कि हम इस सदी में डूबेंगे या तैरेंगे। डा. चंपक राजगोपाल ने बताया कि उदारीकरण के बाद के युग में सशर्त अनुदान और राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाकर शहरों को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित किया गया था।

अतिथियों का स्वागत करते हुए आद्री के प्रोफेसर प्रभात पी घोष ने कहा कि हालांकि भविष्य के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए आलेख एक बहुत ही इनोवेटिव ढांचे में तैयार किए गए हैं।

(अंजनी कुमार वर्मा)

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102
E-mail : adripatna@adriindia.org / adri_patna@hotmail.com, Website : www.adriindia.org